www.tamsasanket.com
वर्षः 05|| अंक 339 || लखनऊ
सोमवार
16 मार्च 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा

दैनिक तमसा संकेत

https://epaper.tamsasanket.com
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 06:13
सूर्यास्तः 06:16
अधिकतमः 33°00
न्यूनतमः 19°00

» पेज 03

विशेष समाचार गैस एजेंसियों द्वारा घरेलू गैस की... » पेज 02 | 'भाजपा के अच्छे दिनों का सिलेंडर... » पेज 04 | जाकिर खान अस्पताल में हुए एडमिट...

भारतीय तीर्थयात्रियों की बस खाई में गिरी

मनाकामना मंदिर से दर्शन कर लौटते समय हादसा

घटना

तमसा संकेत, एजेंसी

काठमांडू। नेपाल के गंडकी प्रांत के गोरखा जिले में शनिवार रात भारतीय तीर्थयात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हैं। यात्री मनाकामना मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक, श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक माइक्रोबस मनकामना मंदिर से लौट रही थी, तभी सड़क से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में घायल 7 यात्रियों को भरतपुर स्थित चितवन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस के अनुसार बस में एक दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे। प्रशासन के अनुसार बस मनाकामना मंदिर से तनहुन

जिले के अंबुखैरेनी इलाके की ओर जा रही थी। घटना के बाद देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। पुलिस ने बताया कि हादसे की दूसरे वजहों की भी जांच की जा रही है। इससे पहले नेपाल के धादिंग जिले में 23 फरवरी को एक पर्यटक बस 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए थे। बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी और उसमें 44 लोग सवार थे। मृतकों में 24 साल का ब्रिटिश नागरिक, 40 साल की चीनी महिला और 32 साल का भारतीय पुरुष भी शामिल हैं। नेपाल में पहाड़ी इलाकों में संकरी सड़कें और खराब सड़क रखरखाव के कारण सड़क दुर्घटनाएं आम हैं।

7 लोगों की मौत | 7 घायल

सड़क दुर्घटनाओं से नेपाल में नुकसान तीन गुना बढ़ा

विश्व बैंक की एक स्टडी के मुताबिक नेपाल में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाला आर्थिक नुकसान 2007 के बाद तीन गुना बढ़ चुका है और अब यह देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) का लगभग 1.5% है। विश्व बैंक के अनुसार नेपाल में सड़क हादसों में मरने वालों में 70% से ज्यादा पैदल यात्री, साइकिल सवार और मोटरसाइकिल चालक जैसे संवेदनशील रोड यूजर होते हैं।

हादसे में बस का ड्राइवर सुरक्षित, सहायक घायल

गोरखा जिला ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के प्रमुख सूरज अर्याल ने बताया कि मृतकों में दो महिलाएं और पांच पुरुष शामिल हैं। सभी भारतीय नागरिक थे। जिला पुलिस प्रमुख भरत बहादुर बीके के अनुसार मृतकों की पहचान मुथु कुमार (58), अनामालिक (58), मीनाक्षी (59), शिवगामी (53), विजयल (57), मीना (58) और तमिलरसी (60) के रूप में हुई है। हिमालयन टाइम्स के मुताबिक, इलेक्ट्रिक बस का ड्राइवर सुरक्षित बच गया, जबकि उसका सहायक इस हादसे में घायल हुआ है।

नेपाल का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी और दुर्गम है। सड़कों के किनारे गहरी खाइयां और ढलान होती हैं। थोड़ी सी गलती या खराब मौसम में वाहन आसानी से सड़क से फिसल सकते हैं, इसलिए सड़क हादसे ज्यादा होते हैं।

घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर

बुछार में ऑपरेशन डीआईजीजीआई-2 जारी

तमसा संकेत, एजेंसी

पुंछ/उरी। कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में 'ऑपरेशन DIGGI-2' के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। यह कार्रवाई तब हुई जब भारतीय सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा यानी LoC के पास कुछ हलचल देखी। इसके बाद सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन चलाया। 14-15 मार्च की रात बुछार इलाके में घुसपैठ कर रहे आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें आतंकी मारा गया। सेना ने आतंकी के पास से हथियार बरामद किए हैं, जिसमें एक AK राइफल, पिस्तौल और गोला-बारूद शामिल हैं। ऑपरेशन फिलहाल जारी है। वहीं, शनिवार को पुंछ में जारी 'ऑपरेशन शेरीकलां' के तहत एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) शहीद हो गया। जवान का नाम सूबेदार संदीप कुमार ढाका है। व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि ढाका सुरनकोटे के ऊबड़-खाबड़ इलाके में ड्यूटी करते समय फिसलकर गिर गए थे। यह ऑपरेशन 18 जनवरी को चतरू बेल्ट के मंडराल-सिंहपोरा के पास सोनार गांव के जंगलों में शुरू किया गया था। पहले एनकाउंटर में 8 जवान घायल हुए थे।

फास्ट न्यूज

नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त

नई दिल्ली। नोएडा की लंबे समय से अटकी स्पोर्ट्स सिटी परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने नोएडा प्राधिकरण को अंतिम मौका देते हुए कहा है कि वह पहले दिए गए आदेशों का पालन करे। कोर्ट ने साफ किया कि परियोजना से जुड़े मामलों में अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

समंदर का पानी पी सकेंगे, लक्षद्वीप में बन रहा प्लांट

कवरत्ती। चारों ओर समुद्र से घिरे द्वीपों की दो सबसे बड़ी चुनौती होती हैं- पीने का मीठा पानी और सस्ती ऊर्जा। लक्षद्वीप में इन दोनों का समाधान समुद्र ही देने वाला है। राजधानी कवरत्ती में ऐसा प्लांट तैयार हो रहा है जो समुद्र के तापमान के अंतर से बिजली पैदा करेगा और उसी प्रक्रिया में समुद्री पानी को पीने के पानी में बदलेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (एनआईओटी) ने ऐसी क्रांतिकारी तकनीक पर काम शुरू किया है, जो इस साल के अंत तक दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी। यह दुनिया का पहला ऐसा हाइब्रिड प्लांट होगा जो समंदर की लहरों से शुद्ध पानी और चौबीसों घंटे बिजली भी पैदा करेगा।

केंद्र के गलत फैसलों के कारण एलपीजी की भारी कमी'

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने रविवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी गलत नीतियों के कारण देश में एलपीजी सिलिंडरों की भारी कमी हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास न तो कोई स्पष्ट योजना थी और न ही समय रहते एहतियाती कदम उठाए गए।

पुजारियों- मुअज्जिनों का मानदेय 500 बढ़ा

चुनाव के ऐलान से सवा घंटे पहले ममता का ट्वीट

2000 मिलेंगे अब हर महीने

बढ़ोतरी

तमसा संकेत, एजेंसी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा से सवा घंटे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुजारियों और मुअज्जिनों (अजान के लिए आवाज देने वाला) के मानदेय में 500 की बढ़ोतरी की है। इन्हें अब हर महीने 2 हजार रुपए मिलेंगे। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया डीए मार्च से देने का ऐलान किया।

» (शेष पेज 04 पर)

सीएम ममता ने रविवार दोपहर एक्स पोस्ट में लिखा- पुजारी और मुअज्जिन समुदायों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार ने मानदेय योजना के तहत पुजारियों और मुअज्जिनों की सभी नई आवेदनों को भी मंजूरी दे दी है।

मांग : शराब नीति मामले में हाईकोर्ट के समन को चुनौती, जज बदलने की मांग, ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके

केजरीवाल-सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे जज को बदलने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। वहीं सिसोदिया ने हाईकोर्ट के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को एक्साइज पॉलिसी केस में डिस्चार्ज (रिहा) कर दिया था। इसी दिन CBI ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। 9 मार्च को हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने CBI की याचिका पर केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब

मांगा था। CBI की अपील पर अब 16 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इसी बीच AAP नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी फिलहाल डिस्चार्ज आदेश पर रोक नहीं चाहती, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहती है।

» (शेष पेज 04 पर)

सीबीआई का दावा- केजरीवाल के करीबी विजय नायर ने साउथ ग्रुप से ₹100 करोड़ वसूले

सीबीआई का दावा है कि केजरीवाल के करीबी विजय नायर दिल्ली एक्साइज बिजनेस के स्टेकहोल्डर्स के संपर्क में थे। वे शराब नीति में उन्हें फायदा देने के बदले पैसों की मांग करते थे। नायर वो जरिया थे, जिन्होंने केजरीवाल के लिए BRS नेता के. कविता की अध्यक्षता वाले साउथ ग्रुप के लोगों से डील की।

जांच अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन पर भी रोक

9 मार्च की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की CBI अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी।

दो पूर्व विधायकों ने चुनाव में पार्टी से पैसे मिलने का दावा किया था

CBI के अनुसार AAP के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले गोवा के दो पूर्व विधायकों ने आरोप लगाया था कि उन्हें एक पार्टी वालंटियर ने चुनाव खर्चों के लिए कैश दिए थे। एजेंसी ने अवैध रुपए लेने और उसके इस्तेमाल के लिए AAP के गोवा प्रभारी दुर्गेश पाठक को भी जिम्मेदार ठहराया है। एजेंसी का दावा है कि शराब नीति के तीन स्टेकहोल्डर्स- शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं का एक गुट तैयार हुआ था। सभी ने अपने-अपने फायदे के लिए नियमों का उल्लंघन किया। BJP ने केजरीवाल-सिसोदिया के बरी होने के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया, जिसमें लिखा है- AAP के पाप अभी पाप धुले नहीं हैं।

यूएई टर्मिनल पर भारतीय जहाज में तेल भरते वक्त हमला

भारत सरकार बोली- स्टाफ सुरक्षित, शिप भी रवाना

तमसा संकेत, एजेंसी

तेल अवीव/तेहरान। अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 16वां दिन है। इस वजह से जहाजों को खाड़ी देशों से ऑयल लाने में दिक्कत हो रही है। भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को UAE के 'फुजैराह ऑयल टर्मिनल' पर हमला हुआ था। » (शेष पेज 04 पर)

ईरान बोला- सुप्रीम लीडर मुजतबा पूरी तरह ठीक

ईरान ने कहा है कि देश के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई पूरी तरह ठीक हैं और उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। इससे पहले ब्रिटिश मीडिया द सन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था। कि मुजतबा 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल के हमले में घायल हो गए थे।

शिर्डी में साईं ट्रस्ट 200 किलो गैस रोज बचा रहा

सोलर सिस्टम से रोज बन रहा 40 हजार श्रद्धालुओं का खाना

तमसा संकेत, एजेंसी

शिर्डी। ईरान-इजराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की आपूर्ति पर दबाव बढ़ने की आशंका है। ऐसे समय में शिर्डी स्थित श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट का सोलर कुकिंग सिस्टम एक मिसाल बन गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाले इस सिस्टम से रोज हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन पकाया जा रहा है।

इस सोलर सिस्टम से हर दिन करीब 2,000 किलो खाना बनाया जाता है, जो लगभग 40 हजार श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त होता है। इससे रोजाना करीब 200 किलो गैस की बचत भी हो रही है। इस अनोखी पहल को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने भी इस प्रोजेक्ट को देश के एक यूनिक मॉडल के रूप में सम्मानित किया है। शिर्डी में रोज

औसतन 75 से 80 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। साईं संस्थान के प्रसादालय में श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन दिया जाता है और लगभग 40 हजार लोग हर दिन इसका लाभ लेते हैं। पहले इतनी बड़ी मात्रा में खाना बनाने के लिए करीब 1,700 किलो गैस खर्च होती थी, जिससे संस्थान पर काफी आर्थिक बोझ पड़ता था।

तमिलनाडु में 23 अप्रैल, असम-केरल-पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग, नतीजे 4 मई को

6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने रविवार को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। बंगाल में दो फेज 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज में चुनाव होंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल, केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा। पांचों राज्यों का रिजल्ट 4 मई को आएगा। 2021 में इन सभी पांच राज्यों के चुनाव का ऐलान 26 फरवरी को किया गया था। पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे। असम में 3 और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी।

पांचों विधानसभाओं का कार्यकाल मई-जून में खत्म हो रहा है। फिलहाल तमिलनाडु में एमके स्टालिन की अगुवाई में DMK की सरकार है, जो 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई। पार्टी ने कांग्रेस, वीसीके और वामपंथी दल के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी ने कई चुनावों में AIADMK जैसे दलों के साथ गठबंधन जरूर किया, लेकिन राज्य में उसकी अपनी सरकार नहीं रही। केरल- दक्षिण का इकलौता राज्य जहां लेफ्ट सत्ता मेंः देश का इकलौता राज्य है, जहां आज भी लेफ्ट सत्ता में है। यहां सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन 2021 में वाम मोर्चा (LDF) ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस गठबंधन की कोशिश इस बार एंटी इनकम्बेंसी को कैश करानी की रहेगी। » (शेष पेज 04 पर)

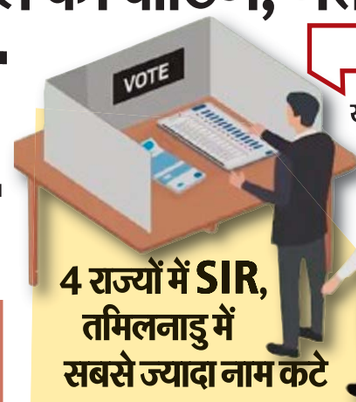

पुडुचेरी- सबसे कम सीटों वाली विधानसभा

2021 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद AINRC-BJP गठबंधन ने सत्ता हासिल की और एन. रंगास्वामी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। यह पहली बार था जब BJP सत्ता में सीधे तौर पर भागीदार बनी। इस बार कांग्रेस DMK के साथ गठबंधन में वापसी की कोशिश कर रही है और सरकार गिरने के मुद्दे को एंटी-इनकम्बेंसी में बदलना चाहती है।

पश्चिम बंगाल- 3 बार से ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री

14 साल से CM ममता के सामने BJP मुख्य चुनौती है। 2026 के चुनाव में टीएमसी जीती तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। वे ऐसा करने वाली देश पहली महिला होंगी। जयललिता के नाम 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। हालांकि, वह 1991 से 2016 तक अलग-अलग कार्यकाल (लगातार नहीं) में मुख्यमंत्री पद पर रहीं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पांच राज्यों-यूटी में 17.4 करोड़ मतदाता हैं। यहां 824 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन राज्यों में आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है।

4 राज्यों में SIR, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नाम कटे

जिन पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें SIR के बाद तमिलनाडु से सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 27 अक्टूबर 2025 को SIR प्रक्रिया शुरू होने के दौरान राज्य में कुल 6,41,14,587 वोटर थे। करीब चार महीने चली SIR में 74,07,207 लोगों के नाम हटाए गए हैं। राज्य में अब 5,67,07,380 मतदाता पंजीकृत हैं। वहीं पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है जहां करीब 58 लाख लोगों के नाम कटे हैं। फिर केरल में 8 लाख, असम में 2 लाख और पुडुचेरी में सबसे कम 77 हजार लोगों के नाम SIR प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से हटाए गए। असम में स्पेशल रिवीजन (SR) कराया गया था।

चुनाव आयोग ने असम और केरल के अनोखे मतदान केंद्र के बारे में बताया

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि असम और केरल के अनोखे मतदान केंद्र भी हैं।

असमः मतदान दल माजुली से 50-60 किलोमीटर की कठिन यात्रा नाव और सड़क मार्ग से तय करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पार करते हैं, और अंत में ट्रैक्टर से दूरस्थ धनेखाना मतदान केंद्र पर 248 मतदाताओं को लेकर पहुंचते हैं।

केरलः इडुक्की जिले के एक आदिवासी क्षेत्र में स्थित बूथ संख्या 34 एडामलकुड्डी, जिसमें कुल 693 मतदाता हैं, और दुर्गम सड़कों से होकर गुजरते हैं, जिसके बाद उन्हें 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।

महाभियोग लाने के सवाल पर बोले सीईसी- इस चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते

TMC संसद में चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई है। इस पर चुनाव आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक नेताओं, दलों के बयानों को लेकर हम किसी भी बातचीत में शामिल नहीं होना चाहते।

आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले कुछ सरकारों के फैसलों को लेकर मैं पहले ही साफ कर चुका हूं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, राज्य और केंद्र सरकारें अपने विवेक से कोई भी नीतिगत और दूसरे निर्णय ले सकती हैं, जो उन्हें उचित लगता हो। लेकिन एक बार जब आचार संहिता लागू हो जाती

तमिलनाडु- भाजपा-कांग्रेस 60 साल से यहां सत्ता में नहीं आ सकीं

आजादी के बाद लगभग दो दशक तक यहां कांग्रेस की सरकार रही। 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई और इसके साथ ही राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आया।

असम- कांग्रेस ने किया 8 पार्टियों से अलायंस

राज्य में 10 साल से भाजपा की सरकार है। पार्टी तीसरे चुनाव की तैयारियों में जुटी है। पीएम मोदी 6 महीने में 3 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। यहां पार्टी ने 126 सीटों में से 100+ सीटें जीतने का टारगेट रखा है। असम में बांग्लादेश, घुसपैठियों/सीमा सुरक्षा, असमिया पहचान जैसे मुद्दे हैं। भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस ने 10 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। इसमें वामपंथी और क्षेत्रीय दल शामिल हैं।

विधानसभा चुनाव 2026

पश्चिम बंगाल - चुनाव शेड्यूल

कुल सीटें- 294 | बहुमत- 148

फेज	सीटें	नॉमिनेशन	स्क्रूटनी	नाम वापसी	वोटिंग	रिजल्ट
फेज 1	152 सीटें	30 मार्च से 6 अप्रैल	7 अप्रैल	9 अप्रैल	23 अप्रैल	4 मई
फेज 2	142 सीटें	2 अप्रैल से 9 अप्रैल	10 अप्रैल	13 अप्रैल	29 अप्रैल	4 मई

सम्पादकीय

दुस्साहस में नहीं आई कोई कमी

इस पर तनिक भी आश्चर्य नहीं कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के चलते ऊर्जा आपूर्ति का संकट उभरते ही देश में रसोई गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई। यद्यपि सरकार ने इसे रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया, पर लगता नहीं कि इससे जमाखोरों और मुनाफाखोरों के दुस्साहस में कोई कमी आई है। इसका प्रमाण यह है कि उनके खिलाफ छापेमारी के दौरान कई शहरों में रसोई गैस सिलिंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले पकड़े गए। कई ने दर्जनों रसोई गैस सिलिंडर चोरी-छिपे जमा कर रखे थे। इनमें कुछ नेता और अन्य प्रभावशाली लोग भी हैं। इसी तरह उन मुनाफाखोरों की गिनती करना भी कठिन है, जो महंगे दामों पर रसोई गैस सिलिंडर बेच रहे थे। ऐसे तत्वों की सक्रियता का एक कारण संबंधित अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत भी होती है। वे भी बहती गंगा में हाथ धोने लगते हैं और इस तरह आम जनता एवं सरकार का संकट बढ़ाते हैं। अपने देश में किसी भी संकट के समय आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी बहुत आम है। कोविड महामारी के समय जब सारा देश संकट में था, तब भी कुछ दवाओं के साथ कई आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी देखने को मिली थी। यह भी किसी से छिपा नहीं कि अपने यहां कभी प्याज, कभी उर्वरकों तो कभी किसी अन्य वस्तु की जमाखोरी होने लगती है। इसका मकसद मुनाफाखोरी करना ही होता है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग सदैव इसकी ताक में रहते हैं कि कब किसी वस्तु के उत्पादन अथवा उसकी आपूर्ति में कमी के आसार दिखें तो वे खुद को जमाखोर में तब्दील कर मुनाफाखोरी करें। आपदा को अपना धंधा बनाने वाले ऐसे लोग सभ्य समाज के शत्रु ही कहे जाएंगे। चूंकि नैतिकता और सदाचार की कमी के चलते जमाखोरी और कालाबाजारी एक सामाजिक बुराई का रूप ले चुकी है, इसलिए आवश्यक केवल यह नहीं कि रसोई गैस सिलिंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी कर रहे लोगों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाए, बल्कि यह भी है कि उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाया जाए। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ उन्हें तीन महीने से लेकर सात वर्ष तक की सजा देने का प्रविधान है, लेकिन आखिर कितने ऐसे मुनाफाखोर हैं, जिन्हें सात वर्ष की सजा मिलती है? अधिकतर तो येन-केन-प्रकारेण बिना किसी दंड के छूट जाते हैं या फिर मामूली जुर्माना देकर बच निकलते हैं। उचित यह होगा कि ऐसे लोगों को ऐसी कठोर सजा दी जाए, जो नजीर बने। गंभीर मामलों में जमाखोरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त की जानी चाहिए। इससे ही मुनाफाखोरों के होश ठिकाने आएंगे और वे जमाखोरी से बाज आएंगे।

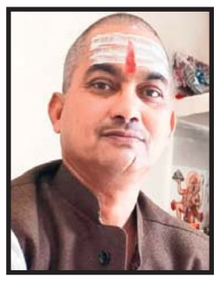

डॉ. उदयराज मिश्र

66
यदि गैस वितरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होने का दावा किया जाता है, तो फिर ऐसी गड़बड़ियाँ कैसे संभव हो रही हैं?

गैस एजेंसियों द्वारा घरेलू गैस की कालाबाज़ारी

कदाचित घरेलू गैस की देश व्यापी किल्लत और मारामारी को देखते हुए दुष्यंत कुमार की उक्त पंक्तियां त्रासदपूर्ण स्थिति को न केवल चरितार्थ रही हैं,अपितु गैस एजेंसियों के मालिकों,सरकारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षकों,प्रशासनिक अधिकारियों और जमाखोरों के गठजोड़ को भी उजागर कर रही हैं।किंतु दुर्भाग्य से चोर चोर मौसेरे भाइयों के बीच पिस रही आम जनता को इस कृत्रिम किल्लत से कब निजात मिलेगी,इस पर अभी भी संशय बना हुआ है।गौरतलब है कि आज आम नागरिक के लिए घरेलू रसोई गैस का सिलेंडर प्राप्त करना भी किसी संघर्ष से कम नहीं रह गया है।

सरकारें भले ही यह दावा करती हों कि देश में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिल रहा है, किंतु जमीनी हकीकत कई स्थानों पर इससे भिन्न दिखाई देती है। गैस एजेंसियों के कुछ संचालकों और उनके डिलीवरी तंत्र द्वारा की जाने वाली कालाबाज़ारी के कारण उपभोक्ताओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि घरेलू गैस की कालाबाज़ारी का एक संगठित तंत्र विकसित हो चुका है। कई स्थानों पर एजेंसी संचालक उपभोक्ताओं के नाम से स्वयं ही गैस बुकिंग कर लेते हैं और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड भी प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद वही सिलेंडर वास्तविक उपभोक्ता तक

पहुँचाने के बजाय खुले बाजार में अधिक कीमत पर बेच दिया जाता है। जब वास्तविक उपभोक्ता सिलेंडर बुक करता है तो उसे या तो बुकिंग में बाधा आती है अथवा यह संदेश मिलता है कि सिलेंडर पहले ही वितरित किया जा चुका है कालाबाज़ारी का दूसरा तरीका यह है कि घरेलू सिलेंडरों को होटल, ढाबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बेचा जाता है। चूँकि घरेलू सिलेंडर की कीमत व्यावसायिक सिलेंडर से कम होती है, इसलिए अधिक लाभ कमाने के लिए कुछ एजेंसियाँ इन्हें गैर-घरेलू उपयोग में बेच देती हैं।

इससे आम उपभोक्ता के हिस्से का सिलेंडर बाजार में गायब हो जाता है और कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई बार एजेंसियों द्वारा यह भी कहा जाता है कि स्टॉक उपलब्ध नहीं है या सप्लाई कम आई है। इस प्रकार कृत्रिम कमी पैदा कर उपभोक्ताओं को विवश किया जाता है कि वे अधिक मूल्य देकर सिलेंडर प्राप्त करें। कहीं-कहीं कम गैस वाले सिलेंडर की आपूर्ति तथा डिलीवरी चार्ज के नाम पर अतिरिक्त धन वसूलने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। यह स्थिति केवल उपभोक्ता के आर्थिक शोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। यदि गैस वितरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होने का दावा किया जाता है, तो फिर ऐसी गड़बड़ियाँ कैसे संभव हो रही हैं? स्पष्ट है कि निगरानी और उत्तरदायित्व की व्यवस्था में कहीं न कहीं ढिलाई है समय की आवश्यकता है कि संबंधित गैस कंपनियाँ और प्रशासनिक अधिकारी इस समस्या को गंभीरता से लें। उपभोक्ताओं की बुकिंग और डिलीवरी की प्रक्रिया की नियमित जांच हो, डिलीवरी के समय ओटीपी या डी ए सी की अनिवार्य पुष्टि हो तथा शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था बनाई जाए। दोषी एजेंसियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी आवश्यक है, तभी इस प्रकार की कालाबाज़ारी पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। घरेलू रसोई गैस किसी विलासिता की वस्तु नहीं, बल्कि आम जनजीवन की मूलभूत आवश्यकता है।

आर्थिक आपदा बनता युद्ध, विश्व की अर्थव्यवस्था के समक्ष खतरा

अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करते हुए ईरान पर जो हमला किया, वह अमेरिकी कानूनों के हिसाब से भी अवैधानिक है। इस युद्ध के कारण विश्व में गैस और तेल का जो संकट पैदा गया है, उसके समाधान का कोई उपाय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास नहीं दिखता। लगता है उन्होंने इस पर कोई विचार ही नहीं किया कि ईरान पर हमले और उसकी जवाबी कार्रवाई से पश्चिम एशिया से ऊर्जा आपूर्ति में जो बाधाएं खड़ी होंगी, उनसे कैसे निपटा जाएगा। ईरान इजरायल के साथ खाड़ी के देशों में अमेरिकी सैनिक अड्डों पर भी हमले कर रहा है और उसने होर्मुज समुद्री मार्ग को भी बाधित कर रखा है, जहां से 20-30 प्रतिशत तेल और गैस की आपूर्ति होती है। ईरान ने होर्मुज मार्ग बंद करने और इस चेतावनी के बाद कि दुनिया 200 डालर प्रति बैरल तक तेल खरीदने के लिए तैयार रहे, यह कहा कि यहां से निकलने वाले जहाजों को हमारी नौसेना को सूचित करना होगा, लेकिन जब तक इस मार्ग से गैस और तेल की आपूर्ति निर्बाध ढंग से नहीं होने लगती, तब तक ऊर्जा संकट के समाधान को लेकर सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता।

चूंकि खाड़ी देश तेल-गैस की आपूर्ति होर्मुज से करते हैं, इसलिए वे ईरान के रवैये पर निर्भर हैं। स्वाभाविक रूप से भारत और चीन जैसे देशों को होर्मुज मार्ग बाधित होने से खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि वे अपने ऊर्जा स्रोतों के लिए एक बड़ी हद तक खाड़ी के देशों पर आश्रित हैं। यह राहत की बात है कि भारतीय प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता के बाद ईरान ने संकेत दिए कि वह भारत के जहाजों को होर्मुज से आने देगा। नई दिल्ली में ईरान के राजदूत ने भी भारत को

मित्र देश बताते हुए ऐसे ही सकारात्मक संकेत दिए और दो भारतीय जहाजों को इस जल मार्ग से आने की इजाजत मिल भी गई, लेकिन यह अभी साफ नहीं कि भविष्य में सभी भारतीय जहाज होर्मुज से बिना किसी परेशानी के गुजरते रह सकते हैं या नहीं? खाड़ी के देशों में तेल और गैस का उत्पादन प्रभावित होने और वहां से उनकी आपूर्ति बाधित होते ही उनके दाम बढ़ने लगे हैं और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के समक्ष खतरा पैदा हो गया है। यह एक नई आर्थिक आपदा बन रहा है। तेल, गैस, उर्वरकों पर निर्भर तमाम भारतीय उद्योगों के समक्ष भी संकट गहराने लगा है। कुछ तो बंद होने की कगार पर हैं या फिर अपना उत्पादन कम करने को विवश हैं। खाड़ी देशों से तेल और गैस की सप्लाई रुक जाने से भारत समेत विश्व भर में महंगाई बढ़ने के साथ ही बेरोजगारी पैदा होने का भी खतरा है। इस खतरे के लिए सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ही उत्तरदायी हैं।

■ संजय गुप्त

सुरक्षा परिषद में कुल...

राजेश श्रीवास्तव

कहां हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन और सुरक्षा परिषद?

इन दिनों दुनिया एक ऐसे सठियाये और सनकी नेता का सामना कर रही है जिसकी सनक ने चहुओंर आतंक मचा रखा है, चाहे कोई भी देश हो, भले ही सुंदरता और अच्छे वातावरण के लिए जाना जाने वाला दुबई हो या फिर सऊदी अरब। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह की सनक हर दिन दिखा रहा है अभी तक टैरिफ का आतंक मचाने वाला यह ट्रंप अब किसी भी देश के राष्ट्रपति को सोते समय पत्नी समेत उठा लेता है तो किसी पर देश पर हमला करके उसके सर्वोच्च नेता को परिवार समेत मार देता है तो किसी देश के उस स्कूल पर बमबारी कर देता है जिसमें २०० बच्चियां पढ़ रही होती हैं। आज इसकी सनक के चलते ही दुनिया के सारे मुल्क परेशान हैं चाहे वह युद्ध में शामिल हों या नहीं, चाहे उनका दूर-दूर तक वास्ता हो या न हो। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर इस ट्रंप पर कोई नकेल कसने वाला है या नहीं, वह भी तब जब खुद अमेरिकी जनता भी उससे अब त्राहिमाम करने लगी है। ऐसे में बस एक ही नाम याद आता है संयुक्त राष्ट्र संगठन और उसकी सुरक्षा परिषद । ऐसे संकट में उम्मीद की जाती है कि ये हस्तक्षेप और मध्यस्थता करे। युद्ध की आशंका को कम करे या फिर रोकने में प्रभावी भूमिका निभाए, युद्ध की त्रासदी और पीड़ा से मुक्ति दिलाए लेकिन पिछले कुछ सालों में चाहें यूक्रेन-रूस का युद्ध हो या अब ईरान-अमेरिका की हालिया जंग, इनकी भूमिका पर सवाल उठ रहा है। ईरान-अमेरिका संघर्ष से तीसरे महायुद्ध की आशंका के बीच सुरक्षा परिषद मूकदर्शक बनी हुई है। 2022 से चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष में सुरक्षा परिषद कोई ठोस कार्रवाई करने में असमर्थ रही है, क्योंकि रूस स्वयं इसका स्थाई सदस्य है। हालांकि,

सुरक्षा परिषद का मूल उद्देश्य महायुद्धों को रोकना था जिसे उसने शीत युद्ध के दौरान और बाद में कुछ हद तक पूरा किया लेकिन वर्तमान भू-राजनीतिक तनाव ने इसकी क्षमता को बहुत सीमित कर दिया है।

ईरान-अमेरिका युद्ध के बढ़ते दायरे के बीच संयुक्त राष्ट्र संगठन और उसकी सुरक्षा परिषद की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं। किसी भी वैश्विक संकट के समय उम्मीद की जाती है कि यह संगठन हस्तक्षेप और मध्यस्थता करे। युद्ध की आशंका को कम करे या फिर रोकने में प्रभावी भूमिका निभा युद्ध की त्रासदी और पीड़ा से मुक्ति दिलाए लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रूस—यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष या ईरान-अमेरिका के ताजा टकराव मामले में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका प्रतीकात्मक ही नजर आती है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 1919 में दुनिया के कुछ देशों ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की थी लेकिन यह संगठन दूसरा विश्वयुद्ध रोकने में नाकाम रहा। दूसरे विश्वयुद्ध के घाव काफी गहरे थे। इसमें पहली बार अणु बम का इस्तेमाल हुआ। नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए इन बमों से हुई असंख्य मौतों और विकिरण के दुष्परिणामों से समूची मानवता विचलित हो गई थी। इस महायुद्ध की अकथनीय पीड़ा ने सीख-सबक दिया कि विवादों-समस्याओं के निदान के लिए युद्ध नहीं शांति का रास्ता खोजना होगा। सवाल था यह कैसे मुमकिन हो? जरूरत महसूस की गई कि इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली मंच हो। इसी मंशा से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई थी। संगठन स्थापना की पहल मित्र राष्ट्रों के प्रमुखों ने की थी। 1945 की सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इस चार्टर के मुख्य उद्देश्यों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सदस्य देशों के मध्य सहयोग बढ़ाना, मानवाधिकारों की रक्षा और आर्थिक- सामाजिक विकास को बढ़ावा देना शामिल हैं। संस्था की सबसे महत्वपूर्ण इकाई सुरक्षा परिषद बनाई गई, जिसे युद्ध और शांति के प्रश्नों पर निर्णय लेने की शक्ति दी गई। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्यों में 5 स्थायी सदस्य हैं बनाए गए, जिन्हें वीटो पावर दी गई। ऐसे पांच देश अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन को मिली शक्ति का यह परिणाम है कि किसी प्रस्ताव का इनमें एक भी विरोध कर दे तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। दूसरे विश्वयुद्ध के विजेता देशों की संगठन में प्रभावी भूमिका के लिए सौंपी गई यह अतिरिक्त शक्ति आगे चलकर संगठन की कमजोरी का कारण बन गईं। जल्द ही संयुक्त राष्ट्र संघ वीटो प्राप्त महाशक्तियों की राजनीति का मंच बन गया।

सोवियत संघ ने 1946-1991 के बीच लगभग 120 बार अपने समर्थक देशों के लिए इस अधिकार का उपयोग किया। अमेरिका ने भी अपने गुट के लिए यही रास्ता अपनाया। नतीजतन कई अंतरराष्ट्रीय संकटों के समय संयुक्त राष्ट्र किसी प्रभावी हस्तक्षेप की स्थिति में नहीं रहा।

जो इस या...

इष्ट देव सांकृत्यायन

गैस की कमी बनाम अधिकता

पता नहीं किन लोगों को भारत में गैस की कमी दिखाई दे रही है। किसी के घर चूल्हा नहीं जल पा रहा तो किसी के होटल में। वह भी उस युग में जबकि मूली बारहमासी हो गई है। भारत के भीतर काम चलाने भर के लिए गैस तो यहीं फेसबुक से पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। यहाँ इतने बुद्धिजीवी हैं, खासकर साहित्यकार-पत्रकार और विश्वविद्यालय आचार्य वर्ग के बुद्धिजीवी।

आप एक बार किसी अच्छे संदर्भ में नाम भर ले लीजिए भाजपा, संघ, मोदी या योगी का... सऊदी अरब के कुएँ भी भाग खड़े होंगे। कभी इस्लामी आतंकवाद की चर्चा करके देखिए। वही गैस तुरंत पेट्रोल में बदल जाएगी। किताबों के नाम पर इतने पैम्फलेट्स का हवाला दिया जाएगा कि तन-मन तो छोड़िए, आत्मा तक का दाह संस्कार हो जाएगा। थीसिस के नाम पर पैम्फलेट लिखने की जो महान परंपरा अंग्रेजों ने डाली थी, उसे महात्मा जी केचेलों ने तो निभाया ही, अपने को पार्टी विद डिफरेंस कहने वाले डॉक्टर जी के चेले भी पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं।

इस पार्टी विद डिफरेंस के लाभार्थी वर्ग के सामने एक बार मोदी की आलोचना करके देख लीजिए।

आपको पता चल जाएगा कि आर्य भले बाहर से न आए हों और चाहे भले ही वेदों का अस्तित्व लाखों साल पुराना हो लेकिन हिंदू तो इस देश में केवल और केवल मोदी के कारण आया। मोदी के पहले न तो सवर्ण था और न ही हिंदू

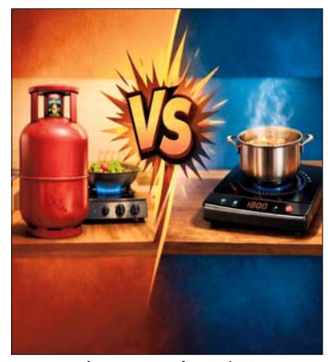

था। यह तो आप जानते ही हैं कि राम को मोदी लाए। अगर गैस से भी पतला कोई फॉर्म होता हो द्रव्य का तो वह भी शर्म से मिट्टी-मिट्टी ही जाएगा उनके तथ्यरोधी तर्कों के सामने।

जो इस या उस गिरोह में न हो, उसे तो बुद्धिजीवी माना नहीं जा सकता। वो बौद्धिक मजदूर भले हो, बुद्धिजीवी नहीं हो सकता और जो बुद्धिजीवी है, उससे आप कभी तथ्य और तर्क की उम्मीद करके देख लीजिए। उससे भी कम पड़े तो रेडियो का कान उमेठिए और मन की बात सुन लीजिए। तन से चाहे चमड़ी पूरी उधड़ गई हो और अब भीतर हड्डी खुरची जा रही हो पर बातों से ही आपके मन पर इतने कंबल डाल दिए जाएंगे कि आपको अपने अस्तित्व पर संदेह होने लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कंबल ही हूँ। उसके बाद जो गैस बनेगी... भाई साहब, अकेले आपकी गैस से पूरे देश का काम चल जाएगा।

एआई के उपयोग से खरीदारी, रोजमर्रा का अनुभव बन रहा बेहतर

पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) महज एक चर्चित शब्द नहीं रहा, बल्कि यह तकनीक से जुड़ी बातचीत का केंद्र बन गया है। हाल ही में आयोजित सीईएस (कंज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स शो) 2026 यह दिखाता है कि हम कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं। अब एआई टीवी और लैपटाप से लेकर घरेलू उपकरणों तक हर श्रेणी का अहम हिस्सा बन चुका है और हर नए संस्करण के साथ ऐसी क्षमताएं सामने ला रहा है, जो रोजमर्रा के अनुभव को वास्तव में बेहतर बनाती हैं। भारत में यह बदलाव एक दिलचस्प रूप ले चुका है। खरीदारी के फैसले लेते समय भारतीय ग्राहक हमेशा से सोच-समझकर और गहन रिसर्च करने वाले रहे हैं। अब एआई उनका रिसर्च पार्टनर बनता जा रहा है, जो जटिलताओं को आसान करता है, सही विकल्प सामने लाता है और आत्मविश्वास के साथ फैसलों की पुष्टि करता है। आज कोई व्यक्ति जब टीवी खरीदने जाता है, तो वह तकनीकी स्पेसिफिकेशंस की भीड़ में नहीं उलझता और न ही थकाने वाली सेल्स पिच सुनता है। इसके बजाय, वह एक एप पर कुछ आसान सवालों के जवाब देता है- कमरा कितना बड़ा है, आप मुख्य रूप से क्या देखते हैं, जगह कितनी रोशनी वाली है।

जेबा खान

जरा हटके

यह धमकी सिर्फ...

डॉ. घनश्याम बादल

तेल के खेल, गैस का दर्द,सियासत और जंग

दुनिया की बड़ी राजनीति अक्सर आम आदमी की छोटी-छोटी ज़रूरतों पर भारी पड़ती रही है। जब कहीं युद्ध की आहट होती है, तो उसके धमाके केवल सीमाओं पर ही नहीं गूंजते, बल्कि रसोई के चूल्हों, पेट्रोल पंपों और घर के बजट में भी सुनाई देने लगते हैं। इन दिनों पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर यही सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर वैश्विक ताकतों की जंग का बोझ कब तक साधारण नागरिक उठाता रहेगा। इजरायल, ईरान और अमेरिका के जंग ने दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्ग हरमुज जलडमरूमध्य को संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। यहां से आपूर्ति रुकने या बाधित होने का असर सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों की जेब पर पड़ रहा है। युद्ध की राजनीति में तेल केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि रणनीतिक हथियार भी बन जाता है। ईरान लंबे समय से यह संकेत देता रहा है कि यदि उस पर सैन्य दबाव बढ़ता है तो वह हरमुज जलडमरूमध्य को बंद करने जैसे क़दम उठा सकता है। यह धमकी सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चेतावनी है। दुनिया के तेल बाजार में ज़रा सी हलचल होते ही कीमतें आसमान छूने लगी हैं। इसका मतलब है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में उछाल, परिवहन महंगा और अंततः हर चीज की कीमत में वृद्धि। यह वही श्रृंखला है जो सीधे आम आदमी के जीवन में आर्थिक दर्द पैदा

करती है। भले ही भारत इस युद्ध का हिस्सेदार नहीं है और न ही यह युद्ध भारत और उसकी सीमाओं के आसपास लड़ा जा रहा है लेकिन फिर भी इस युद्ध के प्रभावों की दृष्टि से भारत इस वैश्विक खेल का एक प्रभावित किरदार है, क्योंकि देश अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से तेल आयात करके पूरा करता है। पश्चिम एशिया में युद्ध या तनाव की हर ख़बर दिल्ली के नीति निर्माताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही है लेकिन विडंबना यह है कि जहां एक ओर वैश्विक संकट का सामना करने के लिए राष्ट्रीय एकता की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर देश के भीतर सियासी बहस अक्सर आरोप-प्रत्यारोप की आग में उलझ रही है। विपक्ष सरकार से सवाल करता है कि तेल और गैस की बढ़ती कीमतों से जनता को राहत क्यों नहीं दी जा रही। सरकार जवाब देती है कि यह वैश्विक बाजार का असर है और भारत ने जितना संभव है संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष सरकार को गैस एजेंसियों के सामने लगी हुई लंबी-लंबी लाइन दिखाकर सवाल खड़े कर रहा है तो सरकार इसे उसकी क्षुद्र राजनीति बता रही है। सच यह है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी राजनीतिक मजबूरियों के साथ खड़े हैं, लेकिन इन बहसों के बीच वह व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान है जो सुबह मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाता है, दोपहर में सब्जी खरीदता है और शाम को सिलेंडर की कीमत का हिसाब लगाता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बड़े-बड़े बयान और टीवी स्टूडियो की बहसें उसके जीवन की वास्तविकता को नहीं बदलतीं। उसके लिए जंग का मतलब है महंगाई, और महंगाई का मतलब है रोजमर्रा की ज़रूरतों पर कुठाराघात। इस पूरे परिदृश्य में सबसे दिलचस्प और विडंबनापूर्ण पहलू यह है कि तेल की वैश्विक राजनीति अक्सर घरेलू सियासत का सबसे सुविधाजनक हथियार बन जाती है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो विपक्ष सरकार पर हमला करता है कि उसने टैक्स कम क्यों नहीं किए। जब कीमतें कुछ कम होती हैं तो सरकार इसे अपनी आर्थिक नीति की सफलता बताती है। लेकिन आम आदमी के लिए यह बहस उस पुरानी कहावत जैसी लगती है जिसमें "हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और" होते हैं। उसे तो बस इतना पता है कि उसका बजट लगातार असंतुलित होता जा रहा है। पश्चिम एशिया की जंग केवल तेल तक सीमित नहीं वरन् वैश्विक कूटनीति, वर्चस्व के लिए चल चला दांव, सैन्य गठबंधनों और शक्ति संतुलन की जटिल कहानी भी है। इज़रायल की सुरक्षा चिंताएं, ईरान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं और अमेरिका की रणनीतिक मौजूदगी- इन तीनों के बीच खिंची रस्साकशी किसी भी क्षण विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। यदि ऐसा हुआ तो उसका असर केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। तेल बाजार में उथल-पुथल, समुद्री व्यापार में बाधा और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता की लहरें दूर-दूर तक महसूस की जाएंगी। भारत के लिए तो चुनौती दोहरी है। एक ओर उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, दूसरी ओर घरेलू आर्थिक स्थिरता बनाए रखनी है। सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, रणनीतिक तेल भंडार और विविध आयात मार्गों की बात ज़रूर की है, लेकिन सच यह भी है कि निकट भविष्य में तेल पर निर्भरता पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है। यही कारण है कि पश्चिम एशिया में हर संकट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए झटका बन जाता है। इन परिस्थितियों में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राजनीति को कम से कम ऐसे मुद्दों पर थोड़ी परिपक्वता नहीं दिखानी चाहिए?

जब वैश्विक संकट सामने हो, तब देश के भीतर संवाद और सहयोग की संस्कृति मज़बूत होनी चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से अक्सर ऐसा नहीं होता। संसद से लेकर सड़क तक, हर जगह आरोपों की ऐसी गूंज सुनाई देती है जिसमें समाधान की आवाज़ न के बराबर और एक दूसरे की टांग खिंचाई कहीं अधिक होती है। आखिरकार जंग का सबसे बड़ा सच यही है कि उसके असली पीड़ित वे लोग होते हैं जिनका उससे सीधा कोई संबंध नहीं होता। तेल की कीमतों में उछाल, गैस सिलेंडर की महंगाई और रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती लागत-ये सब उस अवांछित युद्ध के परिणाम हैं जिसे आम आदमी ने कभी चुना ही नहीं। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की रणनीति का अर्थ सिर्फ इतना है कि उसके घर का बजट और तंग हो गया है।

मेदवेदेव ने 6-3, 7-6 से हराया, विमेंस सिंगल्स के फाइनल में आर्यना सबालेंका पहुंची, रायबाकिना से होगा मुकाबला

इंडियन वेल्स सेमीफाइनल में अल्काराज हारे

मुकाबला

नई दिल्ली, एजेंसी

कैलिफोर्निया में चल रहे इंडियन वेल्स ओपन में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को मेन्स सिंगल्स के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने अल्काराज को सीधे सेटों में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अल्काराज ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन अपने नाम किया था। वहीं, विमेंस सिंगल्स में टॉप सीड आर्यना सबालेंका ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताब के लिए उनका मुकाबला एलिना रायबाकिना से होगा उन्होंने चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा को 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। खिताबी मुकाबले में मेदवेदेव के सामने वर्ल्ड नंबर-2 जैनिक सिनर की चुनौती होगी। सिनर ने दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को एकतरफा अंदाज में 6-2, 6-4 से मात दी। ज्वेरेव ATP मास्टर्स-1000 के सभी नौ टूर्नामेंट में सेमीफाइनल खेलने वाले सिर्फ पांचवें खिलाड़ी हैं। उनसे पहले राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और एंडी मरे यह उपलब्धि हासिल किया था।

कार्लोस अल्काराज साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन अपने नाम किया था।

- सिनर ने दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को एकतरफा अंदाज में 6-2, 6-4 से मात देकर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया।
- आर्यना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में भी एलिना रायबाकिना से भिड़ी थीं।

एलिना रायबाकिना ने स्विटोलिना को मात दी

दूसरे विमेंस सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना ने यूक्रेन की एलिना स्विटोलिना को कड़े मुकाबले में 7-5, 6-4 से हराया। पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच बराबरी की टक्कर देखने को मिली, लेकिन रायबाकिना ने अहम मौकों पर ब्रेक पॉइंट हासिल कर सेट अपने नाम किया। दूसरे सेट में भी उन्होंने अपनी लय बरकरार रखी और जीत हासिल कर सबालेंका के साथ खिताबी भिड़ंत तय की।

जैनिक सिनर से होगा मेदवेदेव का फाइनल मुकाबला

खिताबी मुकाबले में मेदवेदेव के सामने वर्ल्ड नंबर-2 जैनिक सिनर की चुनौती होगी। सिनर ने दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को एकतरफा अंदाज में 6-2, 6-4 से मात दी। ज्वेरेव ATP मास्टर्स-1000 के सभी नौ टूर्नामेंट में सेमीफाइनल खेलने वाले सिर्फ पांचवें खिलाड़ी हैं। उनसे पहले राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और एंडी मरे यह उपलब्धि हासिल किया था।

मेन्स सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में डेनियल मेदवेदेव और कार्लोस अल्काराज 6-3, 7-6(3) से हराया। रूसी खिलाड़ी ने पहले सेट में शुरुआती ब्रेक लेकर मैच पर नियंत्रण बना लिया और पहला सेट 6-3 से अपने नाम किया।

मेदवेदेव ने अल्काराज को संभलने का मौका नहीं दिया

दूसरे सेट में अल्काराज ने वापसी की कोशिश की और खेल को टाई-ब्रेकर तक खींच ले गए। हालांकि, टाई-ब्रेक में मेदवेदेव ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए 7-6(3) से जीत दर्ज की और फाइनल का टिकट पक्का किया। सबालेंका ने लिंडा नोस्कोवा को सीधे सेटों में हराया विमेंस सिंगल्स सेमीफाइनल में बेलारूस की आर्यना सबालेंका का दबदबा देखने को मिला।

केविन पीटरसन ने दिल्ली कैपिटल्स की मेंटरशिप छोड़ी

कहा- समय नहीं दे पाऊंगा, आईपीएल 2026 में कमेंट्री करेंगे पूर्व इंग्लिश कप्तान

नई दिल्ली, एजेंसी

IPL 2026 से पहले केविन पीटरसन ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) की मेंटरशिप छोड़ दी है। पूर्व इंग्लिश कप्तान पीटरसन ने शनिवार को सोशल प्लेटफॉर्म X पर लिखा- 'इस जिम्मेदारी के लिए जितना समय चाहिए, वह नहीं दे पाएंगे।' हालांकि, 45 साल के इस पूर्व बैटर ने दिल्ली की टीम और खिलाड़ियों को नए सीजन के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने यह भी कहा कि वह IPL के दौरान कॉमेंट्री बॉक्स में जरूर नजर आएंगे और भारतीय लीग का हिस्सा बने रहेंगे। पीटरसन को IPL 2025 से पहले दिल्ली कैपिटल्स का मेंटर बनाया गया था। पिछले सीजन में दिल्ली की टीम लीग स्टेज से बाहर हो गई थी।

टीम ने 14 में से 7 मैच जीतकर 5वां स्थान हासिल किया था। लेकिन, प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी थी। पीटरसन बतौर प्लेयर भी दिल्ली की फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं। तब टीम का नाम दिल्ली डेयरडेविल्स था। उन्होंने दिल्ली की ओर से 19 मैचों में 599 रन बनाए हैं। उनकी टीम 2012 के प्लेऑफ में पहुंची थी, लेकिन टाइटल नहीं जीत सकी। 2014 में दिल्ली लीग स्टेज से बाहर हो गई। पीटरसन IPL में पांच सीजन खेल चुके हैं और तीन अलग-अलग टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वह कुल 17 मैचों में कप्तानी भी कर चुके हैं। 2009 में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी की थी, जबकि 2014 में दिल्ली डेयरडेविल्स की कमान संभाली थी।

'धुरंधर 2' ने रिलीज से पहले कमाए ₹27.13 करोड़

पेड प्रीव्यू शो में 5.38 लाख टिकट बिके, 'बाहुबली 2' और 'स्त्री 2' को पीछे छोड़ा

मुंबई, एजेंसी

डायरेक्टर आदित्य धर और एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधरः द रिवेंज' यानी 'धुरंधर 2' ने रिलीज से पहले ही पेड प्रीव्यू में रिकॉर्ड बना दिया। 'धुरंधर 2' ने रिलीज से पहले पेड प्रीव्यू के जरिए करीब 27.13 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने 'दे कॉल हिम ओजी' (23 करोड़) और 'बाहुबली 2' (22 करोड़) को पीछे छोड़ दिया। यह कलेक्शन 'स्त्री 2' के 8.5 करोड़ के मुकाबले लगभग तीन गुना है। आमतौर पर निर्माता प्रदर्शन से पहले दर्शकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए कुछ चुनिंदा पेड प्रीव्यू शो रखते हैं। 19 मार्च को धुरंधर 2 रिलीज होगी। इससे पहले 18 मार्च को देशभर में 9550 पेड प्रीव्यू शो रखे गए हैं। इसकी 5.38 लाख टिकटें बिक चुकी हैं। मुंबई में एक टिकट की कीमत 3100 रुपए तक रही, जबकि दिल्ली में 2400 रुपए रही। इस तरह फिल्म रिलीज से पहले ही भारत में 27.13 करोड़ कमा चुकी है।

यदि पहले से ब्लॉक की गई टिकटों को जोड़ लें तो कमाई 31.9 करोड़ तक पहुंच जाएगी। दुनियाभर में बुक हुए पेड प्रीव्यू शो की कमाई देखें तो यह 60 करोड़ तक पहुंचती है। अमेरिका में 690 स्थानों पर 1765 शो रखे गए हैं। इनके 67 हजार टिकट बुक हो चुके हैं। पूरे उत्तरी अमेरिका में कमाई 13.1 लाख डॉलर (12.12 करोड़) हो चुकी है।

आलिया भट्ट का 33वां जन्मदिन

आलिया भट्ट की 5 फेमस फिल्में

2012 स्टूडेंट ऑफ द ईयर

2014 हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया

2018 राजी

2022 गंगूबाई काठियावाड़ी

2023 रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

पृथ्वीराज चौहान को राष्ट्रपति बताकर मजाक बनीं

आलिया ने नेपोटिज्म और प्रिविलेज को स्वीकार किया

साल 2023 में हार्पर बाजार अरबिया को दिए इंटरव्यू में प्रिविलेज और नेपोटिज्म को लेकर आलिया ने कहा था कि वह इसे मानती हैं और अपने काम को कभी भी हल्के में नहीं लेतीं। वह समझती हैं कि शायद उनके लिए दरवाजे से अंदर आना किसी दूसरे इंसान की तुलना में आसान रहा है।

मुंबई, एजेंसी

वहीं, नेपोटिज्म और ट्रोलिंग को लेकर आलिया ने मिड-डे के साथ बातचीत में यह भी कहा था कि मैं हर बार शब्दों में अपनी सफाई नहीं दे सकती। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं, तो मुझे मत देखिए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लोगों के पास हमेशा कुछ न कुछ कहने के लिए होता है। उम्मीद है कि अपनी फिल्मों के जरिए मैं साबित कर पाऊंगी कि मैं जिस जगह पर हूं, उसकी हकदार हूं। आलिया ने यह भी कहा था कि उन्हें सही जवाब पता था, लेकिन वह जल्दबाजी में दूसरों (सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन) से आगे निकलने की कोशिश कर रही थीं।

उन्होंने कहा था, "मैं पढ़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं हूं, इसलिए कभी-कभी प्रणब मुखर्जी और पृथ्वीराज चौहान के नाम गड़बड़ा देती हूं।"

आलिया ने आलोचनाओं के बावजूद खुद को साबित किया

नेपोटिज्म के आरोपों, नॉलेज को लेकर हुई ट्रोलिंग और सोशल मीडिया पर बने तमाम जोक्स के बावजूद आलिया भट्ट ने अपने 14 साल के करियर में मेहनत और लगातार सफल फिल्मों के जरिए खुद को साबित किया है। आज आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं।

"वहीं, इस मामले को लेकर अगस्त 2014 में आलिया भट्ट ने कॉमेडी ग्रुप एआईबी के साथ मिलकर 'जीनियस ऑफ द ईयर' नाम से एक पैरोडी वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में आलिया ने खुद पर बने मजाक को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश किया। वीडियो में दिखाया गया कि वह एक 'मेंटल जिम' में जाकर अपनी सामान्य जानकारी बढ़ाने की कोशिश करती हैं।"

बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते

अक्टूबर 2025 में आयोजित 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स समारोह में आलिया भट्ट ने फिल्म 'जिगरा' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीतकर रिकार्ड बना दिया और कुल 6 फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड्स हो गए हैं। उन्होंने नूतन और काजोल के 5-5 अवॉर्ड्स का रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए फिल्मफेयर इतिहास में सबसे ज्यादा बार यह पुरस्कार जीतने वाली एक्ट्रेस का खिताब अपने नाम कर लिया।

बॉक्स ऑफिस पर भी हिट

आलिया भट्ट की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। 'ब्रह्मास्त्र' (431 करोड़), 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' (355.61 करोड़), 'गली बॉय' (238.16 करोड़) और दुल्हनिया' (201 करोड़) जैसी कई फिल्में, जिनका हिस्सा आलिया भट्ट रही हैं।

पिता ने कई आउटसाइडर्स को मौका दिया, बेटी नेपोटिज्म पर घिरी

आलिया के पिता महेश भट्ट और उनके बैनर 'विशेष फिल्म्स' प्रोडक्शन हाउस ने बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकारों को बड़ा ब्रेक दिया, जिनका फिल्म इंडस्ट्री से पहले कोई संबंध नहीं था। इन कलाकारों में अनुपम खेर, कंगना रनोट, आशुतोष राणा और बिपाशा बसु जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि, जब महेश भट्ट की बेटी आलिया ने फिल्मों में कदम रखा तो उनके साथ नेपोटिज्म का टैग जुड़ गया। जबकि एक्ट्रेस पूजा भट्ट और राहुल भट्ट उनके सौतेले भाई-बहन हैं। वहीं एक्टर इमरान हाशमी और डायरेक्टर मोहित सूरी उनके कजिन हैं, जबकि प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट उनके चाचा हैं।

जाकिर खान अस्पताल में हुए एडमिट

- अरबाज की पोस्ट पर कमेंट करते हुए यूजर्स ने जाकिर खान की सेहत को लेकर चिंता जताई और उनके जल्द ठीक होने की दुआ की।

मुंबई, एजेंसी

कॉमेडियन जाकिर खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह अस्पताल में भर्ती दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो जाकिर खान के छोटे भाई अरबाज खान ने अपने रमजान व्लॉग में शनिवार को शेयर किया था। व्लॉग में वह दर्शकों को अस्पताल का वह कमरा दिखाते हैं, जहां जाकिर भर्ती हैं। वीडियो में जाकिर एक हॉस्पिटल का गाउन पहने हुए दिख रहे हैं, जिस पर लीलावती हॉस्पिटल का नाम छपा हुआ है। वीडियो में जाकिर और उनके भाई को ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया बनाम इंग्लैंड मैच देखते हुए भी देखा जा सकता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जाकिर 5 मार्च के आसपास अस्पताल में एडमिट हुए। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने का कारण अभी सामने नहीं आया है और यह भी जानकारी सामने नहीं आई है कि वह अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं या नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर सवाल पूछे और जल्द ठीक होने की कामना की। गौरतलब है कि यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब जाकिर ने हाल ही में स्टैंड-अप कॉमेडी से ब्रेक लेने की बात कही थी। जनवरी में हैदराबाद में एक शो के दौरान उन्होंने कहा था।

जेट फ्यूल की कमी से उड़ानों पर असर की आशंका, कीमतें बढ़ने का भी खतरा

ईरान जंग के बीच लंदन में घर खोजना मुश्किल

एक हफ्ते का किराया 3-4 लाख रुपए, लेबनान में 2 लाख बच्चे बेघर

ऑस्ट्रेलिया पर ईंधन संकट का खतरा

बढ़ोतरी

नई दिल्ली, एजेंसी

ऑस्ट्रेलिया में तरल ईंधन की कमी और कीमतों में तेज बढ़ोतरी का खतरा मंडराने लगा है। इसकी मुख्य वजह चीन द्वारा अपनी तेल रिफाइनरियों को ईंधन निर्यात रोकने का निर्देश देना और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रभावित होना बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन परिस्थितियों का असर ऑस्ट्रेलिया की ऊर्जा सुरक्षा और विमानन क्षेत्र पर साफ दिखाई दे सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने अपनी रिफाइनरियों को सभी तरह के ईंधन के निर्यात पर रोक लगाने को कहा है। इससे ऑस्ट्रेलिया के लिए भेजे जाने वाले कम से कम दो ईंधन जहाज प्रभावित हो सकते हैं। इसी बीच पश्चिम एशिया के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दो परिवहन जहाजों के नष्ट होने की खबरों ने भी तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यह मार्ग दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अपने ईंधन का बड़ा हिस्सा एशियाई देशों से आयात करता है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी काफी अहम है। खासतौर पर जेट फ्यूल के मामले में ऑस्ट्रेलिया बाहरी देशों पर लगभग पूरी तरह निर्भर है। वहीं Air New Zealand ने पहले ही ईंधन की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति की अनिश्चितता के कारण करीब 1,100 उड़ानों में कटौती करने का फैसला किया है।

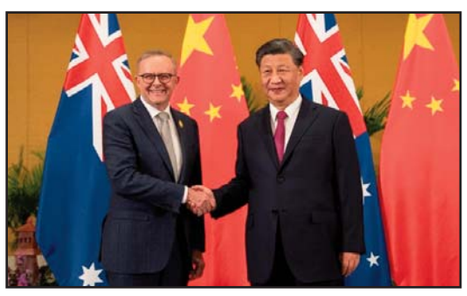

जेट फ्यूल के लिए आयात पर निर्भरता

सिडनी एयरपोर्ट के सीईओ स्कॉट चार्लटन के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया जेट फ्यूल के मामले में पूरी तरह आयात पर निर्भर है। वर्ष 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने जेट फ्यूल का लगभग 32 प्रतिशत चीन से आयात किया था। ऐसे में अगर चीन लंबे समय तक निर्यात बंद रखता है, तो ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया और भारत जैसे देशों से ईंधन मंगवाना पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इन देशों की आपूर्ति क्षमता भी पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रभावित हो सकती है, जिससे वैश्विक स्तर पर ईंधन आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है।

उड़ानों पर पड़ सकता है सीधा असर

ईंधन आपूर्ति में अनिश्चितता का सबसे ज्यादा असर ऑस्ट्रेलिया के विमानन क्षेत्र पर पड़ सकता है। देश के अधिकांश हवाई अड्डे जेट फ्यूल की नियमित आपूर्ति पर निर्भर रहते हैं और उनके पास आमतौर पर केवल कुछ सप्ताह का ही भंडार होता है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख एयरलाइन Qantas ने संकेत दिए हैं कि अगर ईंधन की कीमतें बढ़ती रहीं तो उड़ानों के किराए में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है, हालांकि फिलहाल उड़ानों को रद्द नहीं किया गया है।

देश में सीमित है जेट फ्यूल का भंडार

मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया के पास जेट फ्यूल का भंडार भी सीमित बताया जा रहा है। मार्च 2026 तक देश में लगभग 29 से 32 दिनों का जेट फ्यूल स्टॉक मौजूद है, जो करीब 802 मिलियन लीटर के बराबर है। यह ईंधन या तो देश के भीतर स्थित स्टोरेज टैंकों में रखा गया है या फिर ऑस्ट्रेलियाई समुद्री क्षेत्र में मौजूद जहाजों पर है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के उस नियम का पालन नहीं करता, जिसमें सदस्य देशों को कम से कम 90 दिनों का तेल भंडार रखना जरूरी होता है।

- सीरिया के कमिशली में खुले मैदान में गिरी एक मिसाइल पर एक लड़का चढ़ने की कोशिश करता हुआ।
- इजराइली हमले के बाद लेबनान के बेरूत में सड़क पर बैठा बच्चा। लेबनान में अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं।

तेल अवीव/तेहरान, एजेंसी

अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 16वां दिन है। इस बीच मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण बड़ी संख्या में ब्रिटिश प्रवासी दुबई से वापस लौट रहे हैं। इसके चलते लंदन में किराए के घरों की मांग अचानक बढ़ गई है। डेली मेल के मुताबिक, कई लोग सुरक्षा के कारण जल्दी शिफ्ट होना चाहते हैं और एक हफ्ते के लिए 3 से 4 लाख रुपए तक देने को तैयार हैं। वहीं, हमलों के कारण ईरान में लगभग 20,000 नागरिक इमारतें प्रभावित हुईं, जिसमें 16,000 घर शामिल थे। 77 स्वास्थ्य सुविधाएं क्षतिग्रस्त हुईं, 65 स्कूल तबाह हुए। लेबनान में भी इजराइली हमले जारी है, जिसके कारण करीब 8 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। अल जजीरा के मुताबिक इनमें 2 लाख से ज्यादा बच्चे हैं।

फास्ट न्यूज

हाउस टैक्स के लिए जागरूकता रैली निकाली

लखनऊ। लखनऊ में हाउस टैक्स जमा करने को लेकर नगर निगम जोन- 3 में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जोनल सेनेटरी ऑफिसर मनोज कुमार यादव ने ई-रिक्शा और स्वच्छता वाहनों के माध्यम से 6 वार्डों में जागरूकता रैली निकाली। मौके पर लाउडस्पीकर के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया गया। उनका कहना है। कि 31 मार्च 2026 तक गृहकर जमा कर दें। नहीं तो वित्त वर्ष खत्म होने के बाद में बकाएदारों पर 12 फीसदी ब्याज लगाने का निर्देश दिया।

लखनऊ में ग्रीन बेल्ट पर बनेंगे खूबसूरत पार्क

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना में वर्षों से बेकार पड़ीं ग्रीन बेल्ट अब जल्द ही खूबसूरत पार्कों में बदलेंगी। इन स्थानों को विकसित कर यहां आधुनिक सुविधाओं से लैस पार्क बनाए जाएंगे, जहां लोग सुबह-शाम सैर, व्यायाम और मनोरंजन कर सकेंगे। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है।

योजना के तहत पार्कों में ओपन जिम, बच्चों के लिए झूले और बैठने के लिए आकर्षक स्थान विकसित किए जाएंगे। साथ ही सुंदर लैंडस्कैपिंग, चौड़े पाथवे, आकर्षक लाइटिंग और भव्य प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर वातावरण मिल सके।

मेडिकल छात्रा से ट्रेन में रेप की कोशिश

लखनऊ। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही सबरमती एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट कोच में एमबीबीएस कर रही एक छात्रा से रेप की कोशिश का आरोप है। छात्रा के मां की शिकायत के बाद जीआरपी और आरपीएफ एक्टिव हुई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया 'एक्स' पर शिकायत में छात्रा की मां ने बताया- उनकी बेटी को पानी में नारकोटिक्स और पिज्जा देने की कोशिश की गई। मना करने पर बेटी के साथ में छेड़छाड़ हुई।

सपाई बोले- किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, लखनऊ में उपले बांटे: पुलिस से झड़प

'भाजपा के अच्छे दिनों का सिलेंडर खाली हो गया'

- आवाज लगाकर विधान भवन के सामने उपले बांटते सपाई।
- राम प्रकाश मौर्या ने कहा- भाजपा के अच्छे दिनों का सिलेंडर हुआ खाली।
- महिला पुलिस कर्मियों को भी उपले देने की कोशिश।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में सपाइयों ने LPG गैस की किल्लत के बीच उपले बांट कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। विधान भवन के सामने बापू भवन चौराहे के पास जमीन पर बैठकर ढेर सारे उपले रखकर प्रदर्शनकारी चिल्ला रहे थे- उपले ले लो, उपले ले लो। सपाइयों को उपला बांटता देख मौके पर पुलिस पहुंच गई। प्रदर्शन कर रहे राम प्रकाश मौर्या ने कहा- सिलेंडर की कीमत से आम जनता परेशान है। सरकार को गरीबों की आम जनता की कोई चिंता नहीं है। भाजपा के अच्छे दिनों का सिलेंडर हमारे घरों के किचन से खाली हो गया है। समाजवादी छात्र सभा के लोगों को पुलिस ने उपले बांटने से रोका।

हमारे पास उपलों का भरपूर स्टॉक

हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विधान सभा पर निशुल्क उपले बांट रहे हैं। भारी मात्रा में हमारे पास उपले का स्टॉक मौजूद है। हमने अपने गांव के लोगों से कहकर उपले तैयार करवाए हैं। गांव से लाकर उपले शहरों में बांट रहे हैं। प्रतिदिन अपने गांव से उपले लाकर शहर में बाटेंगे और किसी को भी भूखा नहीं रहने देंगे। भाजपा भूख से तड़पा-तड़पा कर आम जनता को मारना चाहती है। ऐसे संकट के समय में हम देश के साथ खड़े हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी भूखा सोए।

भाजपा सरकार की आंख खोलने का काम करेंगे

प्रवेश यादव ने कहा- घरों से सिलेंडर गायब हो गए हैं। भाजपा के यही अच्छे दिन हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी लाइन लगी हैं। यह बता रहे हैं कि 20 दिन का स्टॉक बचा है। यही अच्छे दिन भाजपा के हैं। हम लोग छात्र हैं। जानते है कि हॉस्टल में और किराए पर रहने वाले छात्रों की स्थिति बेहद खराब है। उनके लिए चुनौती है। कहां से लकड़ी लाएं। कंडे की व्यवस्था करें। अयोध्या जैसी रसोई बंद हो गई। कोई भी एजेंसी देख लीजिए। लंबी-लंबी लाइन लगी है। कंडे की व्यवस्था करके भाजपा सरकार की आंख खोलने का काम करेंगे।

बढ़नी में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन, सपा नेताओं व गणमान्य लोगों की रही मौजूदगी

मानेन्द्र मिश्रा की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में सौहार्द और भाईचारे का दिया गया संदेश

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी शिक्षक सभा सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मणेन्द्र मिश्रा द्वारा शोहरतगढ़ विधानसभा के बढ़नी में रोजा इफ्तार पाटी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाजवादी पाटी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, समाज के सभी लोगों सहित शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने समाज में अमन, चैन और सामाजिक सौहार्द की कामना की।

इफ्तार पार्टी में सर्वश्री नेता विरोधी दल सर्वश्री माता प्रसाद पाण्डेय, पूर्व सांसद कुशल तिवारी, पूर्व विधायक अनिल सिंह, प्रदेश सचिव अजय चौधरी, विधायक प्रतिनिधि डुमरियागंज जहीर मलिक, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मुरली धर मिश्रा, डॉ. सरफराज अंसारी एवं जयकरन गौतम, प्रदेश सचिव राम मिलन भारती, जिला महासचिव कमरुज्जमा, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक शकील शाह, जिला सचिव हरिराम यादव, प्रदेश सचिव जावेद खान, मसूद खान, डॉ. शराफ़ुद्दीन, इफ्तिखार मैनेजर, पूर्व चेयरमैन निसार बागी, पूर्व प्रमुख जाकिर हुसैन, डॉ. इस्तहाक़, राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक इब्राहिम बाबा, जिलाध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ गोपाल फौजी, राष्ट्रीय सचिव छात्र सभा अजय चौरसिया, जोन प्रभारी राकेश दूबे, अकील अहमद उर्फ मुन्नू, सभासद निजाम एवं निसार, सेक्टर प्रभारी हरिनाथ यादव, सेक्टर प्रभारी शफात, विधानसभा अध्यक्ष इटवा बबलू खान, ब्लॉक अध्यक्ष इटवा सुनील यादव, मुस्तफा, जहीर नेता, प्रधान गयासुद्दीन, सोनू यादव जिला सचिव, राकेश कुमार, मुजम्मिल प्रधान, प्रधान सईद आलम दुधवनिया, शादाब, इरशाद, शफीक, वाहिद, डॉ. मोईन, मारूफ खान, मतलूब खान, अब्दुल मन्नान, जलाल, फैजान, करतब यादव, डॉ. खालिद आदि शामिल रहे।

ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा के विद्युत उपकेंद्र मडियाहूं निरीक्षण के बाद जेई निलंबित

उपखंड अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी

- अनुपस्थित रहने और अनियमितता पर सख्त कदम।
- गर्मी के मौसम को देखते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश।

तमसा संकेत, संवाददाता

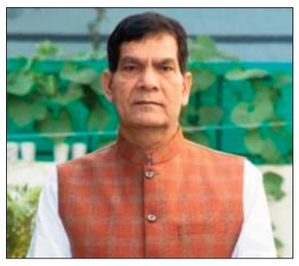

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा के कड़े रुख के बाद जौनपुर जनपद के मडियाहूं विद्युत उपकेंद्र में बड़ी कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान अवर अभियंता (जेई) के अनुपस्थित रहने और कार्यालय में अनियमितताएं पाए जाने पर अधीक्षण अभियंता अनिल पाठक ने अवर अभियंता शहजाद अली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित उपखंड अधिकारी सौरभ तिवारी को भी चार्जशीट जारी की गई है। ऊर्जा मंत्री द्वारा स्पष्ट किया गया कि विद्युत व्यवस्था में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने पाया कि कई अभिलेख और लॉगशीट सही तरीके से भरे नहीं गए थे तथा जिम्मेदार अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं थे। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री श्री शर्मा ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विद्युत विभाग जनसेवा से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने और उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही से जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें।

लखनऊ हाईकोर्ट में 5 दिन डाले वोट, 333 उम्मीदवारों का भाग्य मतपेटी में बंद

यूपी बार काउंसिल चुनाव : आखिरी दिन 82% मतदान

- उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य पद के चुनाव के लिए लखनऊ में पांच दिवसीय मतदान प्रक्रिया रविवार खत्म हो गई।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य पद के चुनाव के लिए लखनऊ में पांच दिवसीय मतदान प्रक्रिया रविवार खत्म हो गई। 11 मार्च से शुरू हुई इस प्रक्रिया में हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने मतदान किया। अंतिम दिन सबसे अधिक करीब 82 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

अब मतगणना के बाद 25 सदस्यीय कमेटी के लिए विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। यूपी बार काउंसिल के

इस चुनाव में लखनऊ में रजिस्टर्ड अधिवक्ताओं को अलग-अलग वर्षों के आधार पर मतदान की तिथि निर्धारित की गई थी। इसी क्रम में प्रतिदिन लगभग साढ़े पांच हजार अधिवक्ताओं को मतदान का अवसर दिया गया। 11 मार्च से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया में पहले दिन सन् 1962 से 2000 तक के रजिस्टर अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद अगले दिनों में अलग-अलग बैच के अधिवक्ताओं ने मतदान किया और 15 मार्च को अंतिम दिन प्रक्रिया पूरी हुई।

प्रदेश स्तर पर होने वाले इस चुनाव में सदस्य पद के लिए कुल 333 अधिवक्ताओं ने नामांकन किया था। हालांकि दो प्रत्याशियों के निधन के बाद अब 331 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं।

जनवरी में हंगामे के कारण टल गया था चुनाव

गौरतलब है कि यूपी बार काउंसिल का चुनाव पहले 27 और 28 जनवरी को प्रस्तावित था, लेकिन उस समय अव्यवस्था और हंगामे की स्थिति के कारण चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद संशोधित कार्यक्रम के तहत लखनऊ में 11 से 15 मार्च के बीच मतदान कराया गया। जबकि लखनऊ में करीब 26 हजार अधिवक्ता इस चुनाव में मतदाता हैं। इनमें से मतगणना के बाद 25 सदस्यीय कमेटी के लिए विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। बड़ी संख्या में उम्मीदवार होने के कारण अधिवक्ताओं के बीच चुनाव को लेकर खासा उत्साह और सक्रियता देखने को मिली।

अब नहीं कराना होगा फूड लाइसेंस का नवीनीकरण

आदर्श व्यापार मंडल ने निर्णय का स्वागत कर, केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष एवं कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स के नॉर्थ जोन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय गुप्ता ने बताया कि फूड कारोबारियो को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से फूड रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराए जाने का प्रावधान है जो एक वर्ष से 5 वर्ष के लिए कराया जा सकता है। किंतु, बहुत बार व्यापारी के ध्यान से उतर जाने पर एक निश्चित अवधि के बाद लाइसेंस रद्द हो जाता था और उसे नया लाइसेंस लेना पड़ता था जिसके लिए पुनः एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता था। 10 मार्च को एक गजट के माध्यम से सरकार ने अब नवीनीकरण को समाप्त कर दिया है अर्थात अब लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसका नवीनीकरण नहीं कराना होगा। व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने आगे बताया कि सरकार ने राहत देते हुए रजिस्ट्रेशन जो कि पूर्व में सालाना 12 लाख टर्न ओवर तक के कारोबारी पर लागू होता था, उसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया है। तथा 5 करोड़ सालाना टर्नओवर के व्यापारी को राज्य से और 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर के व्यापारी को केंद्र से लाइसेंस लेना होता था। इस सीमा को बढ़ाकर अब 50 करोड़ सालाना टर्नओवर तक के व्यापारी राज्य से एवं उससे अधिक टर्नओवर के व्यापारी को केंद्र से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। स्ट्रीट फूड वेंडर्स को राहत देते हुए नए प्रावधान में नगर निगम अथवा स्ट्रीट फूड वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत रजिस्टर्ड स्ट्रीट फूड वेंडर्स को FSSAI के अंतर्गत डीम्ड रजिस्टर्ड माना जाएगा।

ब्राह्मण साथ आए तो सपा बौखलाई: मायावती

समाजवादियों का पीडीए प्रेम छलावा, बीएसपी ही बहुजन की असली पार्टी

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में पूर्व सीएम मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। रविवार को कांशीराम जयंती पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से वोटों की ताकत से सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए एकजुट होने को कहा। उन्होंने कहा कि बसपा ही बहुजन समाज की असली पार्टी है। बाकी सभी पार्टियां स्वार्थ की साथी हैं। कांशीराम जयंती को 'पीडीए दिवस' के रूप में मनाने पर बसपा ने सपा पर हमला बोला। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर कहा- इनका पीडीए प्रेम सिर्फ छलावा है। इन लोगों को इन वर्गों और इनके महापुरुषों की याद सिर्फ चुनाव के वक्त ही आती है। सरकार बन जाने पर वे उन्हें दरकिनार करने में जरा-सा भी वक्त नहीं लगाते। दरअसल, कांशीराम की 92वीं जयंती पर प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज हैं। बसपा ने 'चलो लखनऊ' का नारा देते हुए डॉ. भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें प्रदेशभर से हजारों कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे हैं। जबकि उनकी जयंती को सपा की बाबा साहेब आंबेडकर वाहिनी, 'पीडीए दिवस' के रूप में मना रही। 13 मार्च को कांग्रेस ने भी राजधानी में कांशीराम की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। राहुल गांधी इसमें शामिल हुए थे। कांग्रेस ने कांशीराम को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी पास किया। तय हुआ कि राहुल गांधी संसद में इस प्रस्ताव को रखेंगे। रामबाबू सुदर्शन ने कहा- मान्यवर कांशीराम ने अपना पूरा जीवन वंचित, शोषित, दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित किया। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए लगातार संघर्ष किया।

प्रदेश के 12 मंडलों से लखनऊ आए बसपाई

लखनऊ में डॉ. भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर प्रदेश के 12 मंडलों से पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी ने प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचने की अपील की थी। सोशल मीडिया पर भी '15 मार्च चलो लखनऊ' अभियान चलाया गया।

पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि इस आयोजन के माध्यम से संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की कोशिश की जा रही है। गौतमबुद्ध नगर में भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों

सपा ने कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाया

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी की बाबा साहेब आंबेडकर वाहिनी ने कांशीराम जयंती को 'पीडीए दिवस' के रूप में मना रही है। वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव रामबाबू सुदर्शन ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन में प्रदेश और देशभर में जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर विभिन्न जिलों, नगरों और गांवों में श्रद्धांजलि सभाएं, विचार गोष्ठियां और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे।

मायावती ने एक्स पर लिखा- कांशीराम ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की सोच और मूवमेंट को पूरे देश में जिंदा किया। बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए ऐतिहासिक काम किया। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हमारे सभी कार्यकर्ता बसपा मूवमेंट से जुड़कर मिशनरी और ईमानदार अंबेडकरवादी बनें और अपने वोट की शक्ति से सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करें।

पृष्ठ 01 का शेष...

पुजारियों- मुअज्जिनों...

राज्य में दो फेज 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 मई को रिजल्ट आएगा। ममता ने लिखा कि हम ऐसा माहौल बनाने पर गर्व करते हैं, जहां हर समुदाय और परम्परा को महत्व दिया जाता है और मजबूत किया जाता है। हमारा प्रयास है कि हमारी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के संरक्षकों को उचित सम्मान और समर्थन मिले। सीएम ममता ने ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों से किया गया वादा पूरा करते हुए ROPA 2009 के तहत महंगाई भत्ते (DA) के बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर, शैक्षणिक संस्थानों के लाखों शिक्षक व गैर-शिक्षक कर्मचारी, साथ ही पंचायत, नगरपालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों जैसे अनुदानित संस्थानों के कर्मचारी और पेंशनर को इस फैसला का लाभा मिलेगा। उन्होंने बताया कि ROPA 2009 के DA का बकाया भुगतान मार्च 2026 से शुरू होगा। इसके लिए राज्य के वित्त विभाग की ओर से विस्तृत अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं, जिनमें भुगतान की प्रक्रिया और नियम तय किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद 1 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हुई थी। इसमें वोटर 7.66 करोड़ से घटकर 7,04,59,284 रह गए हैं। यानी SIR से अब तक 63.66 लाख नाम हटे हैं, जो कुल मतदाताओं का 8.3% है। दिसंबर में जारी मसौदा सूची में 58 लाख से अधिक नाम हटे थे। CEO ने कहा- 60 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम की जांच अभी भी जारी है। हालांकि उन्हें नई वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। बाद में इन नामों पर फैसले के बाद लिस्ट में बदलाव हो सकता है। 2021 चुनाव में 294 में 166 सीटों पर जीत का अंतर 25 हजार से कम था। इनमें टीएमसी ने 102, भाजपा ने 64 सीटें जीती थीं। 5,000 से कम अंतर वाली 36 सीटों में भाजपा 22, टीएमसी 13 जीती। ऐसे में एक-एक वोट अहम है। हालांकि 25 हजार से ज्यादा अंतर वाली 111 में 108, 50 हजार से ज्यादा अंतर वाली 43 सीटें टीएमसी जीती थी।

केजरीवाल....

कि ट्रायल कोर्ट का फैसला ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच को प्रभावित न करे। हाईकोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी केस की जांच करने वाले CBI ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लेने के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा दी है। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से बीजेपी शराब घोटाला, शराब घोटाला कर रही थी। हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और हम सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे कि हमें भारतीय न्याय प्रणाली पर भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई। भगवान हमारे साथ है। मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर आजाद भारत का यह सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए हमारी पार्टी के सबसे बड़े पांच नेताओं को जेल में डाल दिया। आज तक आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को घर से घसीटकर जेल में डाला गया और छह महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को दो साल तक जेल में रखा गया। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों पर डिबेट चलती थी, आज देश के सामने कितनी बड़ी समस्याएं हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं उनका समाधान करके सत्ता में आइए न। केजरीवाल पर आम आदमी पर्टी पर झूठे केस क्यों करते हैं। अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और चौबीस घंटे विपक्षियों पर ऊटपटांग झूठे केस करना उन्हें जेल में डालना ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ता। देश तब आगे बढ़ेगा, जब जनता की समस्यों का समाधान किया जाएगा। नायर ने ही शराब नीति में फायदा देने के बदले में साउथ ग्रुप के लोगों से 100 करोड़ वसूले थे। दो अन्य आरोपियों- विनोद चौहान और आशीष माथुर के माध्यम से इन पैसों को गोवा भेजा गया। केजरीवाल के निर्देश पर इस 100 करोड़ की रकम में से 44.5 करोड़ कैश गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किया या। इसलिए केजरीवाल चुनाव के दौरान गलत तरीके से कमाए पैसों का इस्तेमाल करने के भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को ही मिला है। पब्लिक सर्वेंट्स और साजिश में शामिल अन्य आरोपियों को आर्थिक लाभ मिला, लेकिन सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

यूएई टर्मिनल पर...

इस दौरान भारतीय झंडे वाला जहाज 'जग लाड़की' वहां तेल भर रहा था। जहाज पर मौजूद सभी भारतीय स्टॉफ सुरक्षित हैं। जहाज ने लगभग 80,800 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लोड किया और अब सुरक्षित रूप से भारत की ओर रवाना हो गया है। वहीं, ईरान ने रविवार को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी हमले के बाद भी तेल टैंकरों में तेल भरने का काम जारी है। अल जजीरा के मुताबिक वहां एक टैंकर को तेल लोड करते हुए देखा गया है। जहाजों की गतिविधि पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म टैंकरट्रैकर्स के मुताबिक इलाके में और भी कई टैंकर खड़े हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि 5 टैंकर पहले ही फ्यूल ऑयल भर चुके हैं और 2 टैंकर अभी तेल भरने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ये टैंकर किस देश या कंपनी के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल के टुकड़े गिरने से उस इमारत को नुकसान पहुंचा है, जहां अमेरिकी डिप्लोमेट काम करते हैं। हालांकि यह नहीं बताया गया कि यह इमारत किस शहर में है। इजराइल में अमेरिका का दूतावास यरुशलम में है और तेल अवीव में भी उसका एक बड़ा दफ्तर है। इराक में ऑयल एक्सपोर्ट दोबारा शुरू करने को लेकर सरकार के अलग-अलग विभागों में मतभेद सामने आए हैं।

इराक के तेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑयल एक्सपोर्ट फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन कुर्द क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने फिलहाल इससे इनकार कर दिया है। तेल मंत्रालय के मुताबिक, क्षेत्र से तुर्किये के बंदरगाह जेहान तक जाने वाली पाइपलाइन के जरिए रोज करीब 3 लाख बैरल तेल भेजा जा सकता है। इसके अलावा पहले से चल रहे तेल क्षेत्रों से करीब 2 लाख बैरल तेल रोजाना एक्सपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने कुछ शर्तें रखते हुए अभी निर्यात शुरू करने से मना कर दिया है। इस पर तेल मंत्रालय ने कहा कि शर्तों पर बाद में बात की जा सकती है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाने के लिए निर्यात जल्द शुरू होना जरूरी है जयशंकर ने ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच शनिवार को सऊदी अरब और UAE के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। उन्होंने मिडिल ईस्ट की बदलती स्थिति और वहां के हालात पर चर्चा की। ईरान ने रविवार को इस जंग में पहली बार इजराइल पर 'सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल' दागी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा कि इजराइल के सैन्य और डिफेंस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। यह सॉलिड फ्लूय वाली स्ट्रैटेजिक मिसाइल है, जो 2000-2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। यह महत्वपूर्ण सैन्य और कमांड सेंटर्स पर सटीक हमला कर सकती है।

6 राज्यों की 8...

वहीं, BJP अब तक केरल में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां उसने त्रिशूर लोकसभा सीट जीती थी। इसके अलावा दिसंबर 2025 में भी BJP ने पहली बार त्रिवेंद्रम (तिरुवनंतपुरम) नगर निगम का चुनाव जीता।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com
स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।
सम्पादक : विद्यादेवी
समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा
समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676